दैनिक ट्रिब्यून

# मोदी कैबिनेट ने झोंकी ताकत

## आरक्षण आंदोलन के बाद खट्टर का मनोबल बढ़ाने जुटे केंद्र के 7 मंत्री

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा की सूरत पर जो दाग लगा, केंद्र सरकार ने उसे साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां शुरू हुए दो दिवसीय हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में सोमवार को मोदी कैबिनेट के 6 से अधिक मंत्रियों ने निवेशकों के सामने हरियाणा की तारीफों के पूल बांध दिए। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किए गए समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाले मंत्रियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खूब संबल प्रदान किया।

**केंद्र ने बनाया दबाव**

बताया जाता है कि हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के बाद केंद्र की ओर से इस समिट को हर हाल में करने का दबाव बनाया गया और इस आयोजन में केंद्र की ओर से हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद ही केंद्रीय मंत्रियों के आने का कार्यक्रम बना।

सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों हुए

गुड़गांव में सोमवार को हैपनिंग हरियाणा समिट में मौजूद केंद्रीय मंत्री वैंकया नायडू, अरुण जेटली, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। -हप्र

### एनएच 8 पर ही रहा फोकस

समिट में गुड़गांव को चेहरे के तौर पर पेश करके शेष 20 जिलों के लिए भी निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य था लेकिन पहले दिन निवेशकों की राय नेशनल हाईवे नंबर 8 के दोनों ओर बसे जिलों तक आकर अटक गई। दिल्ली से बावल तक गुड़गांव, रेवाड़ी व नारनौल जिले को निवेश के लिए बेहतरीन व उत्तम बताया। यहां मौजूद नेताओं ने अपने भाषण में इसकी पुष्टि भी की।

## पहले दिन साइन हुए 38 एमओयू

**गुड़गांव (हप्र):** समिट के पहले दिन विभिन्न कंपनियों के साथ 38 एमओयू साइन किए गए। इन कंपनियों ने प्रदेश में एक लाख 28 हजार 740 करोड़ रुपये के निवेश के आश्वासन दिया है। इन समझौतों में एम3एम के साथ मिश्रित उपयोग विकास, कार्यालय और परचून तथा स्मार्ट सिटी के सम्बन्ध में हुआ 45 हजार 365 करोड़ रुपये का निवेश का एमओयू, वाटिका लिमिटेड के साथ हुआ 12 हजार 823 करोड़ रुपये निवेश का एमओयू तथा आईआरईओ के साथ 11 हजार 100 करोड़ रुपये का एमओयू शामिल है। इसी तरह से ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ कौशल विकास के लिए 23 करोड़ रुपये का, ऑल कार्गो के साथ 500 करोड़ रुपये का, ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए अलकीमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 680 करोड़ रुपये का, कौशल विकास के लिए ही अमरटैक्स ग्रुप के साथ 125 करोड़ रुपये का, कृषि उपकरणों के लिए बेरी उद्योग के साथ 200 करोड़ रुपये का, खाद्य प्रसंस्करण प्लांट के लिए बूट माल्ट इंडिया होल्डिंग के साथ 552 करोड़ रुपये का भी आज करार किया गया।